राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना एक विश्लेषण

जकी मुमताज*

किसी भी देश के विकास में व्यावसायिक शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व होता है। इसकी सहायता से व्यक्तियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल-प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाता है। इस लेख में समसामयिक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इस लेख में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही, लेख के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन हेतु किए गए प्रयासों का विश्लेषण करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं दिए गए सुझावों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की मुख्यधारा से एकीकृत करने का प्रयास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को क्रियान्वित के पश्चात आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जा सकता है। इसके साथ ही, शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। इस नीति में व्यवस्था है कि विद्यालयों से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ने तथा ऐसे बच्चे जो काम करने के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे।

किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का प्रभाव उसके जीवन स्तर, जीवन दर्शन, कार्य तथा सामाजिक संबंधो को प्रभावित करता है। व्यवसाय किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान होता है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को रोज़गारपरक बनाते हुए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का वह समन्वित रूप है, जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ रोज़गार की तैयारी सतत रूप से कराई जाती है। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट कार्य एवं कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करके उसे कार्य विशेष में निपुण बनाती है और जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है।

**सहायक आचार्य*, महाविद्यालय ऑफ़ टीचर एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462030

देश के विकास में शिक्षा का विशेषकर व्यवसाय से संबंधित विषयों की शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व होता है। भारत में औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि मुख्यधारा की शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसी तरह व्यावसायिक विषय के साथ कक्षा 11 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के पास उच्चतर शिक्षा में अपने व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग स्पष्ट नहीं होता है।

सामान्य शिक्षा के मानदंड ऐसे नहीं थे कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आगे की उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल सके। इसके परिणामस्वरूप वह मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का चयन नहीं करने का कारण यह भी है कि विद्यार्थी विभिन्न व्यावसायों या व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व एवं श्रम की महत्ता से परिचित नहीं हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कई धारणाएँ पहले से चली आ रही हैं। जैसे शारीरिक श्रम को मानसिक श्रम की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने कहा कि सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा की दोहरी व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को केवल गरीबों के लिए देखा जाने लगा है। सामान्य शिक्षा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए तथा व्यावसायिक शिक्षा शेष विद्यार्थियों के लिए है, इस प्रकार का विभाजन शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। यह माना जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, व्यावसायिक शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है। इसी कारण व्यावसायिक शिक्षा को कमतर माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यावसायिक शिक्षा के समक्ष अन्य चुनौतियाँ भी हैं, जैसे— व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों की कमी, नए उभरते क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं का औद्योगिक उपक्रमों के साथ भागीदारी का अभाव, निरंतर कौशल उन्नयन के लिए अवसरों की कमी इत्यादि।

व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव एवं संस्तुतियाँ

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) तथा शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या पर विचार किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की संस्तुति की और सामान्य विषयों के साथ व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने कार्य-अनुभव को बढ़ावा दिया तथा ग्रामीण विद्यालयों में उद्यान-विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा की सिफारिश की। औद्यौगिक क्षेत्रों के लिए तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया और बड़े नगरों के लिए प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना पर सुझाव दिया। शिक्षा आयोग (1964 –1966) ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण किए जाने अर्थात माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने पर बल दिया, जिससे कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन करने तथा व्यवसाय संबंधी

योग्यता एवं कौशलों को सीखने के अवसर प्राप्त हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित तथा सुविचारित नीति की परिकल्पना की गई। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रदान किए जाएँ। कार्ययोजना 1992 में सभी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में एक ही राष्ट्रीय पद्धति अपनाते हुए दक्षता पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गईं। सभी स्तरों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के विकास एवं मार्गदर्शी रूपरेखा प्रदान करने के लिए तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद कार्य करेगी। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए एवं जिला स्तर पर जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए।।

यदि हम वास्तविक रूप से व्यावसायिक शिक्षा का उन्नयन चाहते हैं, तो संस्थाओं में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समाज को इस शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा तथा रोज़गार में कोई तालमेल नहीं है। प्रत्येक वर्ष शिक्षा संस्थाओं से बहुत सारे विद्यार्थी सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोज़गार हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए शिक्षा का व्यावसायीकरण आवश्यक है, जिसमें विद्यार्थियों को किसी व्यवसाय से संबंधित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान समय की माँग है, इसलिए शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार करने के साथ ही, इसकी पुनर्कल्पना की भी आवश्यकता है।

व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए भारत सरकार के प्रयास

भारत में 200 से अधिक संस्थान हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। 19–24 वर्ष के 5 प्रतिशत लोग 12वी पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तहत औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके साथ ही, समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा के व्यावसायीकरण का संचालन हो रहा है, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थी भी इस शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तुलना यदि हमारी कुल जनसंख्या से की जाए, तो अत्यंत कम है, लेकिन सरकार ने जो विभिन्न प्रयास किए हैं, उनकी वजह से इन आँकड़ों में तेज़ी से बदलाव हो रहा है।

सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाईं और उनका कार्यान्वयन भी किया, जैसे— विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए 1988 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा पोषित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1993 में भोपाल में स्थापित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय अनुसंधान तथा विकास संगठन के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान ने छः मुख्य

क्षेत्रों में क्षमता आधारित 82 पाठयक्रम तैयार किए और यह संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री को मानकीकृत करने का कार्य करता है एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। सी.बी.एस.ई. देश भर में 500 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 107 विषयों वाले 34 व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चला रहा है। एन.आई.ओ.एस. अपने मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से 82 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसमें सरकारी संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन तथा सोसाइटी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जन शिक्षण संस्थान, स्वैच्छिक एंजेसियों के माध्यम से 15–35 आयु वर्ग के अशिक्षित, नव-साक्षर, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित, अकुशल एवं बेरोज़गार युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत के युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए उड़ान, कौशल भारत अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इत्यादि जैसी पहलें सम्मिलित हैं।

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना से तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा को पुनः परिभाषित करना है, जिसमें विद्यार्थियों की रुचियों एवं वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार नए व्यावसायिक विषयों तथा कौशलों को सम्मिलित करना है। साथ ही, व्यावहारिक व सहभागिता आधारित शिक्षण विधियों को अपनाना है, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाया जा सके। बदलते समय के साथ उद्योगों की आवश्यकताएँ भी बदलती रहती हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान, कौशल एवं अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार व्यावसायिक शिक्षा में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें।

इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने तथा इसकी पुनर्कल्पना पर बल दिया गया है। यूनिसेफ 2019 के अध्ययन के अनुसार कम से कम 47 प्रतिशत भारतीय युवा 2030 तक आवश्यक शिक्षा एवं कौशल सीखने की गति में उस स्थिति में नहीं है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए।। इसी के साथ यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फ़ॉर इंडिया 2020 में कहा गया है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सामान्यतः विश्वविद्यालय के स्नातकों की तुलना में नौकरी प्राप्त करने में कम समय लगता है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर तक मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जाती रही है और

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे साकार करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, इस बात पर बल दिया गया है कि आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा के काल से ही उच्चतर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से होते हुए, उच्च शिक्षा तक कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकेंगे। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रोचकता पर आधारित गतिविधियाँ कराई जाएँगी। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और आगे उच्च शिक्षा में भी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का अवसर दिया जाएगा।

इस तरह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात कही गई है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि 2025 तक विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा से जुड़े 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से अवगत कराया जाएगा। सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) में अभी तक व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में इस बात को कहा गया है कि अब इन विद्यार्थियों को भी जी.ई.आर. में सम्मिलित किया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार जो बच्चे काम करने के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। ड्राप आउट हो चुके विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस तरह वे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे भी व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर सकें, इस दिशा में सी.बी.एस.ई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) का व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा एन.आई.ओ.एस. मिलकर काम कर रहे हैं।

अब उच्च शिक्षा संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रारंभ कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (B.Voc.) पाठ्यक्रम वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था, इसका अधिक प्रसार हो, इस पर भी बल दिया जाएगा। चार साल के होलिस्टिक बैचलर प्रोग्राम में व्यावसायिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। सभी उच्च शिक्षा के संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ना होगा। इसके लिए नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा तथा उसके तहत व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मैपिंग किया गया है कि विद्यार्थियों को भविष्य में इन पाठ्यक्रमों का लाभ मिल सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा के संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा के स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ करें। वर्तमान में जो विद्यार्थी 10वीं या 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उन्हें आगे उच्च शिक्षा में जाने के अवसर बहुत कम थे, जिससे वह आगे चलकर उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा नहीं ले पाते थे। अब नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया

गया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (शॉर्ट टर्म स्किल प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्सेज) भी संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, स्थानीय फैक्ट्रियों, फर्म, एन.जी.ओ. इत्यादि से जुड़ना होगा, जिससे विद्यार्थियों को इन संस्थाओं के संसाधनों के साथ प्रयोग कर, सीखने के अवसर मिल पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाव दिया गया है, इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी और इसी परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा की समग्र रूप से व्यवस्था की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरी के साथ स्वरोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात कही है। आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा के मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति (N.C.I.V.E.) का गठन किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करने का काम करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एक रुचिकर बात कही गई है, वह लोक विद्या है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को लोक विद्या अर्थात पारंपरिक ज्ञान देने की बात की गई है। उच्च शिक्षा केंद्र विभिन्न उद्योगों के साझेदारी के साथ इनक्यूवेशन सेंटर स्थापित करेंगे, जहाँ विद्यार्थियों को नौकरी और स्वरोज़गार हेतु निर्देशन के अच्छे अवसर मिल सकेंगे। भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आम जनता को सोशल मीडिया तथा आई.सी.टी. के माध्यम से जागरूक किया जाएगा, जिससे उनके देखने एवं सोचने में बदलाव आए। कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को करियर हेतु निर्देशन तथा परामर्श दिया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु कक्षा 8 में ही कौशल पर आधारित दक्षता परीक्षा ली जाएगी। साथ ही, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार निर्देशन दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में पारंपरिक व्यावसायों के अतिरिक्त अब वर्तमान में रोबोटिक, आई. टी. इत्यादि नई तकनीक को भी जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए योग्यता हेतु मानक तैयार किए जाएँगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सेवापूर्व शिक्षकों के लिए अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा किए गए प्रयास

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष और अग्रणी संस्था है। यह संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई

है, जिसे 1993 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया। यह संस्थान पिछले 31 वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है। यह संस्थान शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की नीति नियोजन एवं कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह व सहायता प्रदान करता है। यह भारत में यूनेस्को यूनेवोक नेटवर्क केंद्र (UNESCO UNEVOC Centre) के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे तकनीकी और यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र (International Centre for Technical and Vocational Education and Training of UNESCO) भी कहते हैं। इसका लक्ष्य वर्तमान तथा भविष्य की कौशल आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करना है। संस्थान में कृषि तथा पशुपालन, व्यवसाय एवं वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन, मानविकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान विभाग हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्र जैसे पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र, कार्यक्रम नियोजन एवं निगरानी केंद्र और आई.सी.टी. केंद्र भी हैं। जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, रोज़गार योग्यता तथा 21वीं सदी के कौशल प्रदान करके आजीवन सीखने को बढ़ावा देने, विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। यह संस्थान भारत में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो कि उल्लेखनीय है। इसके द्वारा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा को विकसित किया गया है। इसके साथ ही, संस्थान के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों के कौशल में अभिवृद्धि के लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान की उल्लेखनीय भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—

- संस्थान ने विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व पर बल देता है।
- संस्थान ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए शोध अध्ययन तथा परियोजनाएँ शुरू की हैं।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
- कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थी रोज़गार क्षमता में सुधार करने के लिए मॉडल व्यावसायिक विद्यालय स्थापित करने तथा विद्यालय-उद्योग संबंधों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत संस्थान कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक आकांक्षात्मक वातावरण बनाने

के लिए छह राज्यों में मॉडल व्यावसायिक विद्यालय स्थापित कर रहा है।

- संस्थान ने कक्षा 9 से 12 के लिए रोज़गार कौशल तथा नौकरी-विशिष्ट व्यावसायिक सामग्री के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम का विकास किया है।
- व्यावसायिक शिक्षकों एवं प्रमुख पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रधानाध्यापकों और व्यावसायिक शिक्षकों सहित प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान प्रासंगिक पाठ्यक्रम डिज़ाइन सुनिश्चित करने तथा विद्यालय-उद्योग संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ जोड़ता है।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा 2013 (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देने तथा विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, शिक्षकों के लिए आई.टी., कृषि तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल सीखने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम का आयोजन करना।
- विद्यार्थियों के लिए संसाधनों अर्थात व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तकों को तैयार करना, जैसे ग्रेड 6 के लिए कौशल बोध व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका तैयार की गई।
- यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को सलाह देकर, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री विकसित करके और अनुसंधान करके विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस तरह पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) द्वारा किए जा रहे ये प्रयास भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को भविष्य में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समग्र शिक्षा अभियान तथा व्यावसायिक शिक्षा

समग्र शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जो न केवल विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाने पर बल दिया गया है। इसमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। समग्र का अर्थ, संपूर्ण है इसलिए यह विद्यालयी शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। समग्र शिक्षा योजना 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था।

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हुई, जिसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026

तक किया जाना सुनिश्चित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान को सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) से और राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के साथ जोड़कर एक नया आयाम दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। समग्र शिक्षा अभियान को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक एक सामान समावेशी कक्षा वातावरण के साथ विद्यार्थियों का कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों के बुनियादी ढाँचों में सुधार, रचनात्मक शैक्षणिक विधि, व्यावसायिक शिक्षा, वर्चुअल तथा स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड एवं आई.टी. लैब का प्रावधान किया जाएगा, जिससे 2026 तक शिक्षा में बड़ा परिवर्तन किया जा सके। इस योजना के माध्यम से कम आयु में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षित व आत्मनिर्भर होकर एक बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।

इस अभियान का लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज से सेकेण्डरी स्टेज तक, समान एवं समावेशी कर सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना को लागू कर रहा है। विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के तहत सामान्य शिक्षा के साथ-साथ नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए एक व्यावसायिक विषय की पेशकश की जाती है, ताकि विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक रोज़गार योग्यता तथा व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्ति व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं—

- विद्यालयी पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जैसे— कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि को सम्मिलित किया जाए।
- विद्यालयों को उद्योगों के साथ साझेदारी कर विद्यार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।
- विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वे अपने करियर के बारे में सही निर्णय ले सकें।
- विद्यालयों में प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने की समझ विकसित होगी।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा सकता है, ताकि वे विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण दे सकें।

विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए सुझाव

विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए गए हैं जिन्हें बुनियादी स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा

के लिए अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकता है।

- विद्यार्थियों को प्रारंभिक चरण से ही करियर परामर्श तथा उच्च शिक्षा के मार्गों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इससे उन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने तथा यह समझने में सहायता मिलेगी कि विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा विकल्पों से कैसे जुड़ी है।
- विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा परिसरों, कार्यक्रमों तथा अवसरों से परिचित कराने के लिए कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का नियमित दौरा आयोजित करें, जहाँ विद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से मिल सकेंगे।
- विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों के पाठ्यक्रम में मूलभूत विषयों तथा कौशलों की पहचान कर सम्मिलित किया जाए। एक एकीकृत पाठ्यचर्या ढाँचा बनाया जाए, जहाँ विद्यालयी शिक्षा उच्च शिक्षा विषयों की नींव रखती है, जिससे इंजीनियरिंग, चिकित्सा या मानविकी जैसे विशेष क्षेत्रों में आसानी से प्रगति हो सके। विद्यालयी स्तर पर कुछ विषयों को पहले से ही शुरू कर सकते हैं, जिससे इन विषयों और कौशलों के बुनियादी ज्ञान विद्यार्थी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में इन विषयों को समझना और जोड़ना आसान होगा।
- ऐसे सेतु प्रोग्राम तैयार किए जाएँ जो गणित, विज्ञान और अंग्रेज़ी जैसे विषयों में प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रदान करके विद्यालय से महाविद्यालय तक विद्यार्थियों की सहायता करें।
- विद्यार्थियों को उन्नत अवधारणाओं एवं करियर विकल्पों से अवगत कराने के लिए विद्यालयों में अतिथि व्याख्यान देने या कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसरों और पेशेवरों को आमंत्रित किया जाए।
- विद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी करके अकादमिक क्लब तथा प्रतियोगिताएँ आयोजित करा सकते हैं, जो विद्यार्थियों को उन्नत विषयों एवं विश्वविद्यालय स्तर की चुनौतियों से परिचित कराए।
- ऐसे ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें, जहाँ विद्यालयी विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दोनों ही सामान्य संसाधनों एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकें, जिससे विभिन्न शैक्षिक चरणों में आजीवन सीखने को बढ़ावा मिले। ऐसे डिजिटल परामर्श प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जहाँ विद्यालयी विद्यार्थी, उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सलाहकारों, विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों तथा कैरियर परामर्शदाताओं से बातचीत कर सकें।
- विद्यालयों को कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल टूल और प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने तथा तकनीक-आधारित सीखने में सहायता मिले।
- उच्च शिक्षा स्तर पर उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा विश्वविद्यालयों एवं

उद्योगों के सहयोग से विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट-आधारित सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करें, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न कौशलों पर आधारित उद्योगों में काम करने के अवसर प्रदान किए जा सकें। इससे उन्हें वास्तविक दुनिया का अनुभव तथा व्यावसायिक वातावरण से संबंधित अनुभव प्राप्त हो सकेंगे।

विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक शिक्षा से जोड़ना तथा व्यावसायिक शिक्षा देना

विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक शिक्षा से जोड़ने तथा व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

- विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रेरित करने के लिए काउंसलिंग और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे वे वापिस शिक्षा की ओर लौट सकें। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन विद्यार्थियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ, जिन्होंने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी सफलता प्राप्त करके दिखाई है। विद्यार्थियों को उनके कौशल तथा रुचियों के आधार पर सही करियर के बारे में मार्गदर्शन किया जाए।
- विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें, ताकि वे सरलता से समझ सकें।
- विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करें।
- विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली एवं आसान तरीके से समझने योग्य शिक्षा सामग्री तैयार करना।
- आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, विद्यार्थियों को विभिन्न मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट और कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करें। विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरणों तथा ऑनलाइन शिक्षा सामग्री से जोड़ें, ताकि वे घर बैठे भी सीख सकें। उनके लिए लचीले समय सारणी एवं मिश्रित मॉडल में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कक्षाएँ आरंभ करें, ताकि वे अपनी सुविधा से शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- शिक्षकों को ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, विशेष आवश्यकताओं और मानसिकता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।
- शिक्षकों को ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए छोटे समूहों में पढ़ाई का अवसर दिया जाए, ताकि वे व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त कर सकें।
- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए पुनः प्रवेश कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों के लिए विशेष लर्निंग सेंटर स्थापित करें, जो नियमित विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा।
- शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल, नृत्य एवं कला के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा को तकनीकी और व्यावसायिक

कौशल से जोड़ें। विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार विभिन्न व्यावसायों और कौशलों (जैसे— कढ़ाई, बुनाई, बिजली का काम आदि) की शिक्षा दी जाए और व्यावसायिक शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसरों उपलब्ध कराए जाए या रोज़गार से जोड़ा जाए।

- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे उन्हें अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सहायता मिल सकती है।

इन उपायों को लागू करके हम ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा से जोड़ सकते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए सुझाव

- ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए सरल तथा व्यावहारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करें, जिनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। विद्यार्थियों को केवल तकनीकी, व्यावसायिक कौशल ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल (जैसे, समय प्रबंधन, टीमवर्क आदि) भी सिखाएँ जाएँ।
- स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को उनकी रुचियों तथा कौशल के आधार पर विभिन्न कामों (जैसे, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, प्लंबर आदि) का प्रशिक्षण दें। लड़कियों एवं लड़कों के लिए विशिष्ट कौशल शिक्षा कार्यक्रम तैयार करें, जो उनकी रुचियों तथा सामर्थ्य के अनुसार हों। व्यावसायिक शिक्षा को विद्यार्थियों के समय व स्थिति के अनुसार लचीला बनाएँ, ताकि वे इसे अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों को उनके प्रशिक्षण के बाद रोज़गार के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन किया जाए तथा उन्हें रोज़गार दिलवाने में सहायता करें। विद्यार्थियों को अपने खुद के छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें।
- कम लागत में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाएँ, ताकि वे आर्थिक रूप से असमर्थ होने पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- विद्यार्थियों को उन लोगों के उदाहरण देकर प्रेरित करें, जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है।
- विद्यार्थियों को कंप्यूटर, इंटरनेट तथा डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखाएँ, ताकि वे आधुनिक कार्यों में भी दक्ष हो सकें। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे घर बैठे भी सीख सकें।
- विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के दौरान आर्थिक सहायता (स्टाइपेंड) प्रदान करें, ताकि वे अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकें।

इन सुझावों से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें समाज में रोज़गार योग्य एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विषयों को स्थान दिया

जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, विद्यार्थियों के व्यावसायिक निर्देशन हेतु उचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर सकें तथा उसके लिए आवश्यक तैयारी कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के संबंध में कई प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन व्यवस्थित एवं सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सार्थक रूप से क्रियान्वयन किया जाए, तो विद्यार्थी किसी न किसी व्यवसाय के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल अर्जित कर सकेंगे तथा उन्हें रोज़गार के लिए तैयार किया जा सकेगा, जिससे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान होगा।

संदर्भ

नामबिअर, के.के.वी. 2007. *वोकेशनल स्टडीज़ एंड प्रोडेक्टिव वर्क इन एजुकेशन*. नीलकमल पब्लिकेशन, हैदराबाद.

पाण्डेय, वी.सी. 2005. *इश्यूज़ एंड ट्रेंडस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस*. इशा बुक्स, दिल्ली.

पाठक, पी.डी. 2011. *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ*. अग्रवाल प्रकाशन, आगरा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय, टी. 2008. *वोकेशनल एजुकेशन*. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली.

https://www.researchgate.net/publication/359757796_Vocational_education_in_India_Issues_and_Challenges दिनांक 30 मई 2023 को देखा गया।

https://in.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-vocational-education दिनांक 30 मई 2023 को देखा गया।

https:/samagra.education.gov.in दिनांक 5 मई 2024 को देखा गया।

https://www.psscive.ac.in/ दिनांक 15 मई 2024 को देखा गया।